पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा

डॉ. जगदीप सक्सेना

बजट 2026–27 भारत की कृषि रणनीति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत देता है, जिसमें ग्रामीण विकास के केंद्र में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को रखा गया है। 26.7 प्रतिशत की बढ़ी हुई बजटीय आवंटन राशि के साथ यह बजट पशु स्वास्थ्य, डेयरी अवसंरचना, मत्स्य मूल्य शृंखलाओं और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करता है। पशु चिकित्सा सेवाओं, उद्यमिता, सहकारिताओं, ऋण सुविधा और जलीय कृषि के लिए लक्षित समर्थन का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, ग्रामीण रोजगार सृजित करना और आय में वृद्धि करना है। सामूहिक रूप से ये उपाय 'विकसित भारत' के अनुरूप एक सुदृढ़, समावेशी और निर्यात-उन्मुख ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं।

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ये क्षेत्र केवल आय और रोज़गार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए संकट के समय में 'आर्थिक सुरक्षा कवच' का काम भी करते हैं। विशेष रूप से जब फसल खराब हो जाए या बाज़ार में अनिश्चितता हो, तब दूधारू पशु और मत्स्य पालन ग्रामीण परिवारों को नियमित तथा भरोसेमंद आय प्रदान करते हैं।

केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए इन क्षेत्रों को अधिक संगठित, उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आवंटन तथा नीतिगत पहलों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। बजट का ज़ोर उत्पादकता बढ़ाने, रोज़गार सृजन को गति देने, निर्यात क्षमता मज़बूत करने और उत्पादन से बाज़ार तक पूरी वैल्यूचेन को सुदृढ़ करने पर है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान

भारत में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। ये क्षेत्र ग्रामीण आबादी को रोज़गार, आय और पोषण उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। देश की कुल GDP में केवल डेयरी क्षेत्र का योगदान लगभग 5 प्रतिशत है और यह 8 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का आधार है। इसी प्रकार मत्स्य पालन (मछली पालन) तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार देता है।

लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), नई दिल्ली में प्रधान संपादक रह चुके हैं। ईमेलः jagdeepsaxena@yahoo.com

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया कि किसानों की कुल आय में पशुपालन का योगदान लगभग 16 प्रतिशत है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योगदान और भी अधिक महत्वपूर्ण है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि क्षेत्र की 4.6 प्रतिशत वृद्धि का मुख्य कारण फसलें नहीं, बल्कि पशुपालन और मत्स्य पालन रहे हैं।

बजट आवंटन

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे अधिक बजट वितरण हुआ है। मंत्रालय को कुल ₹8,915.26 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। इसमें से ₹6,153.46 करोड़ पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) के लिए तथा ₹2,761.80 करोड़ मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं।

मत्स्य पालन बजट में से ₹2,530 करोड़ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सीधे मछुआरों और मछली पालकों को सहायता देने के लिए तय किए गए हैं। सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के लिए ₹2,500 करोड़ का अलग से आवंटन किया गया है, ताकि नई पहलों को तेज़ी से लागू किया जा सके।

पशुपालन और डेयरी: प्रमुख योजनाओं में बढ़ोतरी

पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत संचालित प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, ताकि पूरे डेयरी तंत्र को अधिक मज़बूत और आधुनिक बनाया जा सके।

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के लिए ₹2,010 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्य देशभर में चल रहे टीकाकरण अभियानों को जारी रखना और पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करना है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

राष्ट्रीय गोकुल मिशन को ₹800 करोड़ का आवंटन मिला है। इसका उद्देश्य पशुओं की नस्ल में सुधार, आनुवंशिक गुणवत्ता में वृद्धि और देशी नस्लों का संरक्षण व विकास करना है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

इस योजना का बजट बढ़ाकर 1,055 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह राशि मुख्य रूप से दूध शीतकरण *(मिल्क चिलिंग)*, दूध प्रसंस्करण संरचनाओं और सहकारी व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए रखी गई है।

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष

AHIDF* के लिए ₹465 करोड़ का अधिक आवंटन किया गया है। इसका उद्देश्य ब्याज में छूट, ऋण गारंटी जैसी सुविधाएँ देकर डेयरी क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना है। AHIDF के अंतर्गत दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण और पूँजी निवेश ऋण से ऋण की लागत घटेगी। इससे उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और बाज़ार तक, डेयरी वैल्यू-चेन के हर स्तर पर निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

समुद्री मत्स्य पालन: ब्लू इकॉनॉमी का मज़बूत आधार

समुद्री मत्स्य पालन देश की ब्लू इकॉनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूती देता है और लाखों लोगों के लिए पोषण का प्रमुख स्रोत भी है।

भारत के पास 11,099 किलोमीटर लंबा समुद्री तट और लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है। यह क्षेत्र समुद्री मत्स्य संसाधनों के लिए विशाल संभावनाएँ प्रस्तुत करता है। निर्यात आधारित विकास को तेज़ करने के लिए बजट में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण (सीफूड प्रोसेसिंग) की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु कई कदम प्रस्तावित किए गए हैं।

बजट में निर्यात के लिए समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले कुछ निर्धारित इनपुट्स के ड्यूटी-फ्री आयात की सीमा 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है। इससे निर्यातकों को बेहतर गुणवत्ता वाले इनपुट्स कम लागत पर उपलब्ध होंगे और वे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे।

इसके अलावा, यह भी प्रस्ताव किया गया है कि भारतीय जहाज़ों द्वारा EEZ या खुले समुद्र से पकड़ी गई मछली को

*Animal Husbandary Infrastructure Development Fund

शुल्क मुक्त किया जाएगा। साथ ही, यदि ऐसी मछली को विदेशी बंदरगाहों पर उतारा जाता है तो उसे वस्तुओं के निर्यात के रूप में माना जाएगा।

पशु चिकित्सा सेवाएँ और रोज़गार सृजन

पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने पशु चिकित्सा सेवाओं को मज़बूत करने की घोषणा की है। इसके तहत 20,000 से अधिक नए पशु चिकित्सक और संबंधित पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी संदर्भ में निजी क्षेत्र में पशुपालन से जुड़े संस्थानों की स्थापना के लिए ऋण से जुड़ी पूँजी सब्सिडी योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी किया गया है। इसमें पशु चिकित्सा एवं पैरा-वेट कॉलेज, पशु अस्पताल, जाँच प्रयोगशालाएँ और प्रजनन (ब्रीडिंग) केंद्र जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। सरकार भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देगी।

उद्यमिता, वैल्यू-चेन और आसान ऋण

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र ने हाल के वर्षों में तेज़ विकास दर दिखाई है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोज़गार की बड़ी संभावनाएँ मौजूद हैं।

इस क्षमता को ज़मीनी-स्तर तक पहुँचाने के लिए बजट में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कई उपायों की घोषणा की गई है। इनमें शामिल हैं:

- ऋण से जुड़ा सब्सिडी कार्यक्रम
- पशुपालन आधारित उद्यमों का विस्तार और आधुनिकीकरण
- पशुधन, डेयरी और पोल्ट्री से जुड़े एकीकृत वैल्यूचेन का विकास
- पशुधन किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के गठन को प्रोत्साहन।

इन उपायों का उद्देश्य डेयरी किसानों को आधुनिक उपकरण अपनाने में मदद देना, उत्पादकता बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में मज़बूत वैल्यूचेन विकसित करना है। 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य के अनुरूप बजट में डेयरी किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने पर भी विशेष ज़ोर दिया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड

डेयरी किसानों और मछुआरों तक विस्तारित किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बजट में KCC की ऋण सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। साथ ही, जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल KCC जारी करने की सुविधा को भी बढ़ाया गया है। इससे छोटे किसानों के लिए ऋण लेना और अधिक आसान हो जाएगा।

सहकारिता और कर प्रोत्साहन

बजट प्रावधानों के अनुसार, प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा पशु चारा और कपास बीज की आपूर्ति पर अब कर कटौती का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सहकारी समितियों के भीतर किए गए लेन-देन से प्राप्त लाभांश (डिविडेंड) आय को नई कर व्यवस्था में कटौती के रूप में मान्य किया जाएगा।

एक अन्य प्रावधान के तहत, यदि किसी अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी महासंघ को लाभांश आय प्राप्त होती है और वह उसे आगे अपनी सदस्य सहकारी समितियों में वितरित करता है, तो उस लाभांश आय को तीन वर्षों के लिए कर छूट दी जाएगी।

बायोगैस और टिकाऊ विकास

डेयरी क्षेत्र को केंद्रीय उत्पाद शुल्क में भी राहत दी गई है। अब बायोगैस मिश्रित CNG पर शुल्क की गणना करते समय बायोगैस के पूरे मूल्य को बाहर रखा जाएगा। इससे डेयरी क्षेत्र में पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा नए बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।

अंतर्देशीय मत्स्य पालन

भारत में अंतर्देशीय मत्स्य पालन एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें विकास की बड़ी संभावनाएँ हैं। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े अंतर्देशीय जलाशयों के नेटवर्क में से एक है, जो लगभग 31.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। हालाँकि इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए अधिक व्यवस्थित प्रयास आवश्यक हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि मत्स्य पालन की वैल्यूचेन को मज़बूत करने

के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा।

इसका उद्देश्य मछुआरों और मछली पालकों जैसे प्राथमिक उत्पादकों को प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात से जोड़ना है। बाज़ार तक अंतिम-स्तर (लास्ट माइल) तक बेहतर पहुँच मिलने से मछुआरों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। इस पहल के अंतर्गत लगभग 200 स्टार्टअप्स को समर्थन दिया जाएगा और 34 उत्पादन तथा प्रसंस्करण क्लस्टरों को सीधे लाभ मिलेगा।

सरकार जल संरक्षण और आजीविका से जुड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 69,000 अमृत सरोवर विकसित कर चुकी है। इनमें 1200 से अधिक ऐसे सरोवर भी शामिल हैं जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं।

महिलाओं द्वारा संचालित मछली किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इनके लिए बाज़ार से बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उनकी सौदेबाजी की क्षमता बढ़े और उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकें। मछली सहकारी समितियों, FFPOs और स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए किए गए एकीकृत प्रयासों से तटीय क्षेत्रों में लगभग 50 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

निर्यात, मूल्य संवर्धन और भविष्य की दिशा

हाल के वर्षों में समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात पर दिए गए विशेष ज़ोर का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया है। इससे इस क्षेत्र की वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और भारत की पहचान एक प्रमुख वैश्विक सीफूड निर्यातक देश के रूप में और मज़बूत हुई है। तटीय जलीय कृषि में उत्पादन, विशेष रूप से झींगा पालन, पिछले एक दशक में लगभग तीन गुना हो गया है। यह इस बात का संकेत है कि इस क्षेत्र में उद्यमियों, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

बजट में प्रस्तावित उपायों से भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मज़बूत होने की उम्मीद है। इससे मूल्य संवर्धन (वैल्यू-एडिशन) और उत्पाद विविधता बढ़ेगी तथा देश की विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होगी।

चुनौतियाँ और संभावनाएँ

बजट के आवंटन, प्राथमिकताओं और पहलों की योजना बनाते समय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बताए गए मुद्दों और बाधाओं को भी ध्यान में रखा गया है।

उदाहरण के लिए, पशु चारे की कमी को दूर करने के लिए चारा-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही, पशु चिकित्सा ढाँचे को मज़बूत करने के लिए एक विशेष योजना लाने का प्रस्ताव है ताकि पशु चिकित्सकों की लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर किया जा सके।

कुल मिलाकर बजट के कई प्रावधान जैसे मूल्य संवर्धन पर ज़ोर, पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कोल्डचेन विकास और आसान ऋण सुविधा–श्वेतक्रांति 2.0 को गति देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2026-27 में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों को जिस स्तर पर प्राथमिकता दी गई है, वह यह संकेत देता है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के वास्तविक 'विकास इंजन' को मज़बूती देने के लिए गंभीर है।

बढ़ा हुआ बजट आवंटन, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सहकारिता और निजी निवेश को प्रोत्साहन, वैल्यूचेन सुदृढ़ीकरण तथा निर्यात उन्मुख उपाय–ये सभी मिलकर इन क्षेत्रों को अधिक संगठित, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

यदि इन पहलों का ज़मीनी-स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है, तो पशुधन उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि, कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी, ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों की आय में सुधार तथा डेयरी उत्पादों और समुद्री खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा में वृद्धि की प्रबल संभावना है।

कुल मिलाकर, यह बजट 'विकसित भारत' के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण भारत में रोज़गार, आय और पोषण सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत करता है। ❑